गंगा और यमुना नदियों से जल

465. श्री महाराज सिंह भारती : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश की गंगा और यमुना नदियों से हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान को इस समय कितना जल दिया जा रहा है;

(ख) भविष्य में जल की सप्लाई बढ़ाने के लिये बनाई गई योजनाओं का ब्योरा क्या है, जल की कितनी मात्रा बढ़ाने का विचार है या यह मात्रा कब तक उपलब्ध होने लगेगी; और

(ग) क्या सरकार का विचार जल का समुचित उपयोग करने, विभाग में कार्य-कुशलता और सहयोग स्थापित करने तथा उन अनेक राज्यों के क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुसार, जिनकी उक्त नदियों के जल से सिंचाई की जायेगी, जल का वितरण करने के हेतु गंगा यमुना निगम की स्थापना करने का है?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख). विवरण सभा पटल पर रखा गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या LT-391/67]

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

गंगा नदी पर बांध

466. श्री महाराज सिंह भारती : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के हिमालय क्षेत्र में गंगा नदी पर कितने बांध बनाने का विचार है जिनके लिये सर्वेक्षण किया जा चुका है;

(ख) उनमें से कितने बांधों से लाभ कमाया जाएगा और कितने बांधों से लाभ प्राप्त नहीं होगा; और

(ग) इन सब बांधों के बन जाने पर कितनी अतिरिक्त सिंचाई और विद्युत् क्षमता उपलब्ध होगी और इस कार्य पर अनुमानतः कितना व्यय होगा?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) से (ग). उत्तर प्रदेश की सरकार उत्तर प्रदेश के हिमालयी क्षेत्र में गंगाबेसिन के कई बांध स्थलों पर सर्वेक्षण और अनुसंधान कर रही है। इन स्थलों का अनुसंधान अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इस लिये इस क्षेत्र में बनाये जा सकने वाले बांधों की संख्या इस समय नहीं बताई जा सकती। जब सर्वेक्षण और अनुसंधान पूरे हो जायेंगे और बांधों के निर्माण के लिये खाका प्रस्ताव तैयार हो जायेंगे, तब ही इन परियोजनाओं से होने वाले लाभों को निर्धारित किया जा सकता है और आर्थिक पक्षों का मूल्यांकन किया जा सकता है।

रामगंगा परियोजना

467. श्री महाराज सिंह भारती : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में रामगंगा परियोजना का कार्य कब से आरम्भ हुआ है, उसके सम्बन्ध में क्या अनुमान क्या था और उस पर अब तक कितनी धनराशि खर्च हो चुकी है;

(ख) क्या 2 मई, 1967 से इस बांध के मजदूर हड़ताल पर हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० क० ल० राव) : (क) रामगंगा परियोजना पर काम सितम्बर 1961 से चल रहा है। आरम्भ में इस परियोजना की अनुमित लागत 39.83 करोड़ रुपये थी। पुनरीक्षित अनुमित लागत 92.41 करोड़ रुपये है। इस परियोजना पर मार्च 1967 तक व्यय हुई रकम 31 करोड़ रुपए है।

(ख) और (ग). कर्मकों ने परियोजना अधिकारियों को ये मांगें करते हुये नोटिस दिया कि (1) वर्कचार्ज नोकरों की मजदूरी में वृद्धि की जाए, (2) 20% स्थल मुआवजा भत्ता दिया जाए, (3) कुछ सुविधाओं को बहाल किया जाये (4) वर्कचार्ज कर्मचारियों को बिजली और पानी की मुफ्त सप्लाई की जाए। जब तक स्थायी सलाहकारी बोर्ड, जिसको यह मामला पहले ही निर्दिष्ट किया गया है, अपनी सिफारिशें नहीं दे देता, राज्य सरकार ने वर्कचार्ज नोकरों की मजदूरी में 10% की एतदर्थ वृद्धि करना स्वीकार कर लिया है और यह वृद्धि 10 रुपये से कम और 25 रुपये से अधिक नहीं होगी। किन्तु कर्मकों को इससे सन्तोष नहीं हुआ और वे 3-5-67 से हड़ताल पर हैं।

Subsidy to West Bengal

466. **Shri Tridib Kumar Chaudhuri:** Will the Minister of Finance be pleased to state whether it is a fact that the Central Government have refused to pay any subsidy to the Government of West Bengal to make up for the States loss to the extent of Rs. 4.5 crores in the purchase of a lakh tonnes of rice at increased rates in order to keep up its rationing commitments for the city of Calcutta and other statutorily rationed areas in West Bengal?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): No formal proposal has been received from the Government of West Bengal regarding payment of subsidy to cover the State Government's loss in meeting its commitments in the statutorily rationed areas of West Bengal. The question of refusal does not therefore arise.

Hospitals in West Delhi

469. **Shri Bal Raj Madhok:** Will the Minister of Health and Family Planning be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is not a single General Hospital in the whole of West Delhi and Najafgarh Road Colonies which have a total population of over four lakhs;

(b) if so, whether Government have any plan to open a General Hospital to cater to the needs of West Delhi Colonies; and

(c) if so, the time likely to be taken to get these plans implemented?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri B. S. Murthy): (a) There are small Municipal Hospitals with a total bed strength of 104 beds in these colonies.

(b) and (c). There is a proposal to have a 100 bed hospital in the last year of the Fourth Plan. Land has been acquired for the purpose. The Employees State Insurance Corporation also propose to establish a hospital in West Delhi for their beneficiaries.